



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---------|--|
| सं. 84] | नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 8, 2019/माघ 19, 1940 |
| No. 84] | NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 8, 2019/MAGHA 19, 1940 |

आवासन और शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 99(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास (संशोधन) नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सरकार साधारण पूल आवासिक वास नियम, 2017 के नियम 33 में,—
 - (1) खंड (क) में, उपखंड (i) से उपखंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—
 - उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सचिवालय के मामले में तीन एककों से अनधिक;
 - राज्य सभा के अध्यक्ष के मामले में तीन एककों से अनधिक;
 - लोक सभा अध्यक्ष के मामले में तीन एककों से अनधिक;
 - मंत्रिमंडल सदस्य के मामले में तीन एककों से अनधिक;
 - राज्य मंत्री के मामले में दो एककों से अनधिक; और;
 - भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के मामले में सात एककों से अनधिक;”;

(2) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और कि उपराष्ट्रपति सचिवालय में कार्यरत प्रमुख पदधारियों को पूर्विकता के आधार पर आबंटन शेष बारह साधारण पूल आवासिक वास एककों का कोटा एक टाइप नीचे प्रवर्ग में किया जाना जारी रहेगा।”

[फा. सं. 12035/22/2000-नीति.II(जिल्द.II)]

नंदिता गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण.— मूल नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 16 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 989(अ), तारीख 1 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DIRECTORATE OF ESTATES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

G.S.R. 99(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following amendments to the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Government General Pool Residential Accommodation (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Government General Pool Residential Accommodation Rules, 2017, in rule 33,—

(1) in clause (a), for sub-clauses (i) to (iv), the following shall be substituted, namely:—

- “(i) not exceeding three units in the case of Vice-President, Vice-President Secretariat;
- (ii) not exceeding three units in the case of Chairman, Rajya Sabha;
- (iii) not exceeding three units in the case of Speaker, Lok Sabha;
- (iv) not exceeding three units in the case of Cabinet Minister;
- (v) not exceeding two units in the case of Minister of State; and
- (vi) not exceeding seven units in the case of Chief Justice of India;”;

(2) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the quota of remaining twelve General Pool Residential units for allotment on priority basis to the key officials working in the Vice-President Secretariat will continue to be made in one type below category.”.

[F.No. 12035/22/2000-Pol.II(Vol.II)]

NANDITA GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 598(E), dated the 16th June, 2017 and corrigendum vide notification number G.S.R. 989(E), dated 1st August, 2017.